It is very unfair on the part of NOIDA not to keep up its promise. Hundreds of Central Government employees with their meagre incomes deposited money in the hope that they would get houses, but after some time the money was returned to them. Sir what happened in the meantime is that some other Housing Schemes of DDA came, but these persons did not avail of the opportunity. Now these persons would neither get houses from NOIDA nor from DDA. If NOIDA had not come up with its scheme, all these persons would have got themselves registered with DDA and got houses.

Now, Sir, I would request the Minister to press NOIDA to allot houses to all the persons who had registered their names under the 1979 Scheme. It is very essential from the legal point of view and also from the moral point of view. I have full confidence that the Minister would do justice to the Central Government employees and others who have registered with the Housing Board.

REFERENCE TO THE NEED FOR INCREASE IN FAMILY PENSION UNDER THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACT, 1952.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman Sir, I thank you for kindly permitting me to raise an issue which has been hanging fire for a long time. A memorandum, I think, has been received by almost all the Members of both the Houses regarding the Family Pension Scheme operating under the Employees' Provident Fund Act, 1952. The memorandum has been given by the Textile Labour Association. And incidentally this issue was raised by the memorialists through a petition to the Petition Committee of the House. The Petition Committee gave its findings with recommendations on this memorandum on 1 th September, 1981. That is, this issue has already been considered by the competent Committee of this House. I would draw the attention of the Labour Minister to the recommendations of this Committee. The findings of this Committee are like this, that the pension received under the Family Pension Scheme is pitiably low. The Petitions Committee expressed satisfaction that the minimum has been raised from Rs. 40 to Rs. 60. That is after the date of the order the pension accruing to the members of the family, either widow or the next of kin, has been raised. But it has been pointed in the latest memorandum that this raising of the minimum is meaningless in view of the fact that in actual practice the pension received by them continues to be from Rs. 9 to Rs. 20 or even as low as Rs. 3, and because of certain law, the minimum amount prescribed lately by the Ministry of Labour as Rs. 60 is not available to those who are entitled to receive it. So, this is the situation which, it goes without saying, is highly deplorable. The Ministry of Labour should be seized of this problem, which has the benefit of the advice, the findings, of the Petition Committee, should expeditiously go into this matter and immediately take steps to increase the amount of pension which is pitiably low.

REFERENCE TO THE REPORTED INDEFINITE CLOSURE OF COTTON MILLS LTD., KANPUR.

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आपकी अनुमति से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले का उल्लेख करना चाहता हूं। कानपुर महानगर स्थित जे० के० मैनुफक्चरंज काटन मिल लिमिटेड अक्तूबर, 1976 से प्रबंधकों द्वारा बिना किसी कारण के बन्द कर दिया था। लगभग ढाई हजार बेकारी व भुखमरी में तमाम तरीकों की यातनायें भुगत रहे है। पिछले 6 वर्षों से यह मिल बन्द पड़ी हुई है। मार्च, 1977 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त

[श्री नरेन्द्र सिंह]

तिवारी ने उस पर कुछ प्रयास किया था और उनके प्रयास से वहां के मजदूरों को एक पक्ष का आधा वेतन मिला था और मिल मालिकों ने कुछ इस तरीके का भी दिखावा शुरु कर दिया था कि यह मामला बहुत जल्दी हल किया जायेगा, लेकिन 1977 में हुए लोक सभा चुनावों के बाद मिल के मालिकों को बिल्कुल छूट मिल गई और उन्होंने मिल को बन्द कर दिया। इस बीच इस 6 वर्ष के दौरान लगभग 25 श्रमिकों ने या उनके परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ऐसी भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और लगभग ढाई हजार मजदूरों में से ढाई सौ मजदूर या उनके परिवारों के लोग अभी तक भुखमरी के कारण बेरोजगारी के कारण मर चुके हैं; स्वर्गवासी हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने है। मजदूरों का उस पीरियड का वेतन और ग्रेच्युटी सवेतन अवकाश का करीब 2 करोड़ रुपया मिल पर बकाया है। अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, श्रमिकों, के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही हैं और उनकी जवान बेटियाँ है उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इस गंभीर स्थिति से वे लोग गुजर रहे हैं। मान्यवर यह जो प्रबंधक हैं जानबूझ कर मिल नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास धन न हो, पैसा न हो जिस की वजह से यह मिल को न चला सकते हों हकीकत यह है कि जे० के० प्रतिष्ठान की पूंजी इस बीच बहुत बढ़ी है। उनके पास पूंजी की कोईकमी नही है, उनके पास पैसा है मिल क वे चला सकते हैं मगर चलाना नहीं चाहते है। मान्यवर, इन परिस्थितियों में सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि मिल को चालू कराया जाये। अगर मिल चालू न हो सके तो एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि इन पूंजीपती लोगों की एक नीति है जिसमें ये लोग इस तरह का ढंग अख्तियार करते हैं कि जो मिल पुरानी हो जाती है उस मिल को सिक करके बन्द कर देते हैं और वे उसकी जगह पर दूसरी कोई मिल लगा लेते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जो दो करोड़ रूपये का बकाया मजदूरों का है वह दिलाया जाये, मिल को चालू कराया जाये और मिल के प्रबंधक यदि मिल को न चालू करे तो सरकार उस मिल की ले कर खुद चलाये। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है और नयी-नयी मिलों को लगा रहे हैं। अगर ये लोग इस मिल को नहीं चलाते है तो इस प्रतिष्ठान को या किसी और भी प्रतिष्ठान को कोई नया लाइसेंस न दिया जाय तथा इन मजदूरों की दिक्कत को जल्दी से जल्दी दूर किया जाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिये इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

REFERENCE TO THE REPORTED EXPLOSION AT THE NUCLEAR FUEL COMPLEX AT HYDERABAD

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, I am grateful to you for giving me this opportunity to draw the attention of the Prime Minister to a serious explosion causing considerable damage to machinery and equipment in the zircaloy sponge plant of the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad which took place on last Friday, the 26th March, 1982. It is a matter of regret that an explosion of a serious nature should take place after eight years of similar type of explosion having taken place and which is likely to affect our two major nuclear plants, the supply of which is made through this for Madras and Rajasthan—the